

उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग--3

संख्या 588/XVIII(3)/2016-02(06)/2016 देहरादून, 10 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 46 की उपधारा—(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद द्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 46 की उपधारा—(1) में संदर्भित भूमि के क्षेत्र की सीमा शहरी क्षेत्रों में 20 (बीस) हेक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्रों में 40 (चालीस) हेक्टेयर होगी।

डी०एस० गर्ब्याल, व सचिव। In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 588/ XVIII(III)/2016-02(06)/2016, Dehradun, dated October 10, 2016 for general information:

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND REVENUE SECTION-3

No. 588/XVIII(III)/2016-02(06)/2016

Dated Dehradun, October 10, 2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 46 of the Right to Fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No.30 f 2013), the State Government, hereby, notifies that in limit of extent of land referred to in sub-section 1) of section 46 of the said Act shall be 20 (twenty) hectares in urban areas and 40 (forty) hectares in tral areas.

By Order,
D.S. GARBYAL,
Secretary.

०एस०यू० (आर०ई०) ३४ राजस्व / 530—2016—100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

ता

舍:

में

चित .

को

तकर

हेतु

र्जन,

2013

(च),

ादस्त